

‘अल्पसंख्यक कल्याण हेतु प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम’ और ‘सच्चर समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन’ के विभिन्न मुद्दों का प्रचार करने वाली सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मीडिया यूनिटों द्वारा चलाए गए प्रचार पर की गई कार्रवाई नोट

अक्टूबर-दिसम्बर 2020

पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)

- पीआईबी प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम और सच्चर समिति की सिफारिशों के तहत अल्पसंख्यकों के कल्याण से जुड़े विभिन्न विषयों पर नियमित रूप से विज्ञप्तियां/फीचर जारी करता है।
- इसके विभिन्न क्षेत्रों से इस विषय पर 227 प्रेस विज्ञप्तियां जारी की गईं।

लोक सम्पर्क और संचार ब्यूरो (बीओसी)

➤ *प्रिंट विज्ञापन*

- ब्यूरो अल्पसंख्यक कल्याण से संबंधित विषयों पर अखिल भारतीय आधार पर समय-समय पर विज्ञापन जारी करता रहा है जिनमें उनके लिए उपलब्ध भारत सरकार की विभिन्न स्कीमों, निधियों, छात्रवृत्तियों आदि की जानकारी दी जाती है।
- बीओसी ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की ओर से तिमाही के दौरान “छात्रवृत्ति” और “हुनर हाट” विषय पर कई समाचार पत्रों में 4 विज्ञापन जारी किए।

➤ *बाह्य प्रचार अभियान*

- बीओसी ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की ओर से दिल्ली के लिए 19,57,767 रु. के प्रतिबद्ध व्यय के साथ “हुनर हाट” विषय पर एक विज्ञापन जारी किया।

➤ *क्षेत्र प्रचार*

- चालू कोविड-19 महामारी के कारण बीओसी के सभी फील्ड लोक संपर्क ब्यूरो (एफओबी) और क्षेत्रीय लोकसंपर्क ब्यूरो (आरओबी) ने सामाजिक दूरी की आवश्यकता, आरोग्य सेतु एप की महत्ता, घर में संगरोध कब होना है, कोरोना टेस्ट को कब करवाना है, नियमित हाथ धोना एवं बार-बार सैनेटाइज करना, मास्क को सही तरीके से पहनना और जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं आदि जैसे विषयों पर सोशल मीडिया के विभिन्न साधनों के माध्यम से अल्पसंख्यक केंद्रित क्षेत्रों को शामिल करते हुए जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया।
- आयोजित किए गए जागरूकता कार्यक्रमों के विषयों में कोविड-19, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान, आत्मनिर्भर भारत, होनरिंग द होनेस्ट : फेसलेस असेसमेंट ऑफ डायरेक्ट टेक्स, एक भारत

श्रेष्ठ भारत, प्रधानमंत्री जन धन योजना, आत्मनिर्भर भारत, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, नई शिक्षा नीति 2020 और पोषण अभियान सहित भारत सरकार के निर्णयों और पहलों को शामिल किया गया था।

- ब्यूरो ने देशभर में अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में जन समुदाय के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए डिजिटल माध्यम का उपयोग किया।
- सोशल मीडिया/डिजिटल कार्यक्रमों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

फेसबुक पोस्ट की कुल संख्या	ट्विटर एवं री ट्विटर (इंप्रेशन के साथ) की संख्या	वाट्सएप पर परिचालित पोस्टरों/संदेश/वीडियो की कुल संख्या	इंस्टाग्राम पोस्ट की कुल संख्या	वेबीनार की कुल संख्या
10377	11614	218551 (340532)	1629	108

- अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, सिलिगुड़ी, त्रिवेंद्रम और विजयवाड़ा के तहत फील्ड लोक संपर्क ब्यूरो ने कोविड विजय रथ, मोबाइल वैन/ ऑटो रिक्शा और मोबाइल प्रदर्शनी के माध्यम से 23 कोविड जागृति रथ/ मोबाइल वैन जागरूकता अभियानों का भी आयोजन किया।

आकाशवाणी

- सभी आकाशवाणी केंद्रों ने 'अल्पसंख्यक कल्याण' पर उपयुक्त कार्यक्रमों को तैयार करके इस विषय का व्यापक प्रचार किया।
- विभिन्न स्वरूपों का उपयोग किया गया जिसमें- लघु चर्चा, वार्ता, साक्षात्कार, कम्पीयरिंग, स्पोर्ट, जिंगल आदि शामिल थे।
- कार्यक्रमों में मुख्यतः 15 सूत्री कार्यक्रम के विभिन्न घटकों और सचचर समिति की रिपोर्ट के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया गया।
- तिमाही के दौरान आकाशवाणी केंद्रों द्वारा कुल 1364 कार्यक्रम प्रसारित किए गए।

दूरदर्शन

- देश भर के विभिन्न दूरदर्शन केंद्रों ने विभिन्न स्वरूपों के माध्यम से अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम और सचचर समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर कार्यक्रम प्रसारित किए।
- कार्यक्रमों के प्रारूप में लाइव चर्चा, फोन-इन, स्टूडियो आधारित साक्षात्कार, वृत्तचित्र, सकारात्मक कहानी आदि शामिल थे।
- तिमाही के दौरान दूरदर्शन केंद्रों द्वारा कुल 275 कार्यक्रमों का प्रसारण किया गया।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय
अक्टूबर से दिसंबर 2020 तक राज्य-वार तिमाही प्रगति रिपोर्ट (क्यूपीआर)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	पीआईबी द्वारा जारी प्रेस रिलीज	आकाशवाणी द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों की संख्या	बीओसी द्वारा प्रिंट मीडिया पर खर्च (रु. में)	डीडी द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों की संख्या
1	अण्डमान और निकोबार	-	-	0	-
2	आंध्र प्रदेश	15	15	15,394	3
3	तेलंगाना	-	-	30,788	-
4	अरुणाचल प्रदेश	-	-	0	-
5	असम	15	160	38,760	8
6	बिहार	11	15	32,919	4
7	चंडीगढ़	-	-	23,691	-
8	छत्तीसगढ़	3	-	1,09,500	10
9	मध्य प्रदेश	7	-	1,41,044	-
10	दादरा और नगर हवेली	-	-	0	-
11	दमन और दीव	-	-	0	-
12	गुजरात	14	156	41,853	75
13	जम्मू और कश्मीर	-	-	20,137	-
14	झारखंड	-	27	71,766	1
15	कर्नाटक	16	237	0	-
16	केरल	-	317	28,569	11
17	लक्षद्वीप	-	-	0	-

18	महाराष्ट्र	24	18	3,26,530	-
19	गोवा	-	-	15,014	-
20	मिजोरम	-	25	0	-
21	मेघालय	-	16	10,700	3
22	त्रिपुरा	12	-	8,030	8
23	नागालैंड	-	-	15,394	-
24	मणिपुर	-	9	15,394	7
25	पंजाब	15	113	2,08,921	125
26	हिमाचल प्रदेश	4	-	15,394	4
27	हरियाणा	-	13	13,320	-
28	दिल्ली	15	-	10,01,710	-
29	ओडिशा	-	78	1,59,386	5
30	पुडुचेरी	-	41	0	-
31	राजस्थान	30	-	3,71,324	5
32	तमिलनाडु	-	106	21,400	-
33	उत्तराखंड	-	-	48,510	-
34	उत्तर प्रदेश	31	-	3,42,173	4
35	पश्चिम बंगाल	-	18	72,222	2
36	सिक्किम	15	-	25,840	-